- 19th Year
- Issue: 215
- 09.12.2025 (TUESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे के लिए झुकी इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा-पीएम नरेंद्र मोदी

नयी दिल्ली ०८/१२ (संवाददाता): संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में की। वंदे मातरम् का जो जन-जन से जुड़ाव था, वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक लंबी गाथा की अभिव्यक्ति बन जाता है। जब भी किसी नदी की चर्चा होती है, तो उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा-प्रवाह, एक विकास-यात्रा की धारा-प्रवाह, एक जन-जीवन की धारा-प्रवाह स्वत: जुड़ जाती है। लेकिन ज़्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी की जंग की पूरी यात्रा वंदे मातरम् की भावनाओं से होकर गुजरती थी? ऐसा भाव-काव्य शायद दुनिया में कहीं उपलज्ध नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरज़ की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे के लिए झुकी इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा... दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी हैं।

जिस प्रकार के सपने लेकर वे आए थे, उन्हें यह साफ दिखने लगा कि जब तक भारत को बांटा नहीं जाएगा, लोगों को आपस में लड़ाया नहीं जाएगा, तब तक यहां राज करना कठिन है। तब अंग्रेज़ों ने 'बांटो और राज करो' का रास्ता चुना, और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, तो वंदे मातरम् चट्टान की तरह खड़ा रहा। यह नारा गली-गली का स्वर बन गया। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के माध्यम से भारत को कमजोर करने की दिशा पकड़ ली थी, लेकिन वंदे मातरम् अंग्रेजों के लिए चुनौती और देश के लिए शक्ति की चट्टान बनता गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में लिखित वंदे मातरम् जब देश की ऊर्जा और प्रेरणा का मंत्र बन रहा था और स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया था, तब मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति और मोहज़्मद अली जिन्ना के दबाव में कांग्रेस झुक गई। उन्होंने कहा, ''तब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों पर करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, वंदे मातरम के प्रति खुद की और कांग्रेस पार्टी की निष्ठा को प्रकट करते, उसके बजाय उन्होंने वंदे मातरम् की ही पड़ताल शुरू कर दी।

बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम् गली-गली का नारा बन गया था, और यही नारा बंगाल को प्रेरणा देता था।1907 में जब वी.ओ. चिदंबरम पिल्लै ने स्वदेशी कंपनी का जहाज बनाया, तब उस पर भी 'वंदे मातरज़' लिखा था। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम् का तमिल में अनुवाद किया। अंग्रेजों ने अखबारों पर रोक लगा दी, तो मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में एक अखबार निकाला, और उसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तज़्त पर चढ़ जाते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम् कहते थे। खुदीराम बोस, अशफ़ाक उल्ला ख़ान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ीज़ हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम् कहते हुए फांसी को चूम लिया। यह अलग-अलग जेलों में होता था, लेकिन सबका एक ही मंत्र था, वंदे मातरम। चटगांव की स्वराज क्रांति में जिन युवाओं ने अंग्रेजों को चुनौती दी, वो भी इतिहास के चमकते हुए नाम थे। मास्टर सूर्यसेन को 1934 में जब फांसी दी गई तब उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा और पत्र में एक ही शज़्द की गूंज थी और वह शज़्द था, वंदे मातरम।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्ना के विरोध के पांच दिन बाद ही तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा और उसमें जिन्ना की भावना से सहमति जताते हुए कहा ''वंदे मातरम की आनंद मठ की पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट (क्षुज़्ध) कर सकती है।'' इसके बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम् के उपयोग की समीक्षा की घोषणा की जिससे पूरा देश हैरान था। मोदी ने कहा, ''देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकालीं, वंदे मातरम् गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अज़्टूबर (1937) को कांग्रेस ने वंदे मातरम् पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम् के टुकड़े करने के फैसले में नकाब यह पहना गया कि यह तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में यह किया।

हमारा सपना है कि 2047 में देश विकसित भारत बनकर रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई देश की आजादी का सपना देख सकता था तो 25 साल पहले हम भी समृज़्द्ध, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। मोदी ने कहा कि यहां कोई पक्ष, विपक्ष नहीं है। यहां बैठे हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय है कि आजादी के आंदोलन के परिणामस्वरूप हम यहां बैठे हैं। हम जन प्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के ऋण को स्वीकार करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् की रचना और इसके राष्ट्र गीत बनने में पश्चिम बंगाल की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया और उनका मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो देश भी टूट जाएगा। उन्होंने कहा, 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। जब उन्होंने यह पाप किया तब वंदे मातरम् चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली-गली का नाद बन गया था।

1 करोड़ के इनामी नज़्सली रामधेर मज्जी ने गिरोह के साथ किया सरेंडर

नयी दिल्ली ०८/१२ (संवाददाता): कुज़्यात नज़्सली कमांडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर (सीसीएम) रामधर मज्जी ने सोमवार को अपने ग्रुप के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे हिडमा जैसा ही माना जाता था। उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। मज्जी ने छज़्तीसगढ़ बकर कट्टा थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। एमएमसी ज़ोन में सक्रिय सीसी (सेंट्रल कमेटी) सदस्य मज्जी अपने डिवीजनल कमेटी सदस्यों के साथ पहुँचे और एके-47 राइफल सहित हथियार डाल दिए। उनके साथ, एसीएम रामसिंह दादा और एसीएम सुकेश पोट्टम ने भी अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने एके-47, इंसास राइफल, एसएलआर, .303 राइफल और 0.30 कार्बाइन सहित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद होने की पुष्टि की है। आत्मसमर्पण करने वालों में छह महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं, जो माओवादी आंदोलन में महिलाओं की गहरी भागीदारी को उजागर करता है। इस सूची में लक्ष्मी, शीला, योगिता, कविता और सागर के साथ-साथ डीवीसीएम (डिवीजनल कमेटी सदस्य) ललिता और डीवीसीएम जानकी भी शामिल हैं। अन्य प्रमुख नामों में डीवीसीएम चंदू उसेंडी और डीवीसीएम प्रेम शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनके आत्मसमर्पण से क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क को करारा झटका लगा है। पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया है कि यह समूह महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छज़्तीसगढ़ विशेष क्षेत्रीय समिति क्षेत्र में सक्रिय था, जहाँ वे अपनी गतिविधियाँ संचालित करते थे और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए लगातार खतरा पैदा करते थे।

वो जिन्ना के चश्मे से वंदे मातरम को देखते हैं, संसद में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर अटैक

नयी दिल्ली ०८/१२ (संवाददाता): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा को संबोधित किया और कहा कि राष्ट्रगान राष्ट्र की धड़कन और दुनिया भर में एक मंत्र बन गया है। लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र में बोलते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि 1906 में भारत का पहला झंडा बनाया गया था, और उस झंडे के केंद्र में वंदे मातरम लिखा गया था, जिसे पहली बार बंगाल में फहराया गया था। अगस्त 1906 में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया गया था। यह वह समय था जब वंदे मातरम केवल एक शज़्द नहीं था, यह एक भावना, प्रेरणा का स्रोत और एक कविता थी।

राजनाथ ने कहा कि वंदे मातरम अपने आप में पूर्ण है और इसे अपूर्ण बनाने के कई प्रयास किए गए। वंदे मातरम को उसका गौरव लौटाना समय की मांग है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा आज़ादी के बाद वंदे मातरम को हाशिए पर रखा गया और उसे वह न्याय नहीं मिला जिसका वह हक़दार था।

राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि वंदे मातरम सिर्फ़ बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल पूर्व से पश्चिम तक होता था, और सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी लोग इसका जाप करते थे।

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का एज़्शन शुरू! बीएलओ की मौत का भी याचिका में उठाया गया मुद्दा

नयी दिल्ली ०८/१२ (संवाददाता): एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तमिलनाडु और बंगाल में एसआईआर विरोधी याचिकाएं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर जवाब-तलब किया है। आज अहम सुनवाई इस पर होनी है। तमिलनाडु बंगाल में याचिका दाखिल की गई है। बंगाल के भी कई नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दायर की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पहले ही निर्धारित कर दी थी।

केरल के मामलों की सुनवाई 2 दिसंबर को तमिलनाडु के मामलों की सुनवाई 4 दिसंबर को और पश्चिम बंगाल के मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई। सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में 23 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मृत्यु हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक विस्तृत जवाब मांगा था। राज्य चुनाव आयोगों और चुनाव आयोग दोनों से जवाब देने का आदेश दिया गया।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे तनाव के बीच, मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जानबूझकर देरी करके बंगाल के विकास को धीमा करने का आरोप लगाया और सभी जिलों के अधिकारियों से शांति और प्रगति दोनों को पटरी पर बनाए रखने का आग्रह किया। बंगाल के सबसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में से एक, कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा कि पथश्री परियोजना, जिसका उद्देश्य लगभग 20,000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करना है, के तहत काम एसआईआर प्रक्रिया के कारण नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा, विकास एक सतत प्रक्रिया है।

वंदे मातरम पर नेहरू की आलोचना को लेकर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर किया पलटवार

नयी दिल्ली ०८/१२ (संवाददाता): कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसदीय बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें विकृतियों का उस्ताद करार दिया। कांग्रेस सांसद ने लिखा कि किस भारतीय नेता ने 2009 में अपनी किताब में जिन्ना की प्रशंसा की थी? भाजपा की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के नेतृत्व वाली प्रगतिशील गठबंधन सरकार में विज़ मंत्री के रूप में शामिल हुए और एक साल से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया।

लालकृष्ण आडवाणी ने 2005 में कराची का दौरा किया था और जिन्ना मकबरे की आगंतुक पुस्तिका में एक संदेश लिखा था।

ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में इतिहास रचते हैं। कायदे-आज़म मोहज़्मद अली जिन्ना ऐसे ही एक दुर्लभ व्यक्ति थे।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख हस्ती, सरोजिनी नायडू ने श्री जिन्ना को हिंदू-मुस्लिम एकता का राजदूत बताया था। 11 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा को दिया गया उनका संबोधन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन राज्य आस्था के आधार पर एक नागरिक और दूसरे के बीच कोई भेद नहीं करेगा।

रमेश की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति की आलोचना करने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत से समझौता किया और मुस्लिम लीग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों को डीजीसीए की बनाई हाई लेवल कमेटी ने भेजा समन

नयी दिल्ली ०८/१२ (संवाददाता): इंडिगो के उड़ान संचालन में बड़े पैमाने पर व्यवधान की जाँच कर रहा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नियुक्त पैनल एयरलाइन के मुज़्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और मुज़्य परिचालन अधिकारी इसिड्रे पोरक्वेरस को पूछताछ के लिए तलब किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विमानन नियामक सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और पूरे नेटवर्क में यात्रियों को हुई भारी असुविधा के कारणों की जाँच कड़ी कर रहा है।चार सदस्यीय समिति को परिचालन विफलता के मूल कारणों की पहचान करने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें संयुक्त महानिदेशक संजय ब्रह्मणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कपिल मांगलिक और एफओआई लोकेश रामपाल शामिल हैं। यह पैनल जनशक्ति नियोजन, परिवर्तनशील ज़रू रोस्टरिंग प्रणालियों और पायलटों के लिए नवीनतम ड्यूटी अवधि और विश्राम मानदंडों को लागू करने के लिए एयरलाइन की तत्परता की बारीकी से जाँच करेगा।डीजीसीए प्रमुख फैज़ अहमद किदवई द्वारा 5 दिसंबर को घोषित, यह पैनल इंडिगो द्वारा संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा प्रावधानों के अनुपालन की भी समीक्षा करेगा। इसमें एयरलाइन द्वारा स्वीकार की गई कमियों का आकलन और व्यापक व्यवधानों के परिणामस्वरूप योजनागत विफलताओं के लिए जवाबदेही तय करना शामिल है। पैनल द्वारा इंडिगो के मुज़्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और मुज़्य परिचालन अधिकारी इसिड्रे पोरक्वेरास को बुधवार को एयरलाइन की उड़ान सेवाओं में इतने बड़े पैमाने पर व्यवधान की चल रही जाँच के तहत तलब किए जाने की संभावना है। इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों को ष्तष्ट की बनाई हाई लेवल कमेटी ने भेजा समन, 6 दिनों रद्द हुई 3900 ज़्लाइटों के संबंध में सवाल जवाब किए जाएंगे

०८/१२ (संवाददाता): इंडिगो के उड़ान संचालन में बड़े पैमाने पर व्यवधान की जाँच कर रहा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नियुक्त पैनल एयरलाइन के मुज़्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और मुज़्य परिचालन अधिकारी इसिड्रे पोरक्वेरस को पूछताछ के लिए तलब किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विमानन नियामक सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और पूरे नेटवर्क में यात्रियों को हुई भारी असुविधा के कारणों की जाँच कड़ी कर रहा है।चार सदस्यीय समिति को परिचालन विफलता के मूल कारणों की पहचान करने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें संयुक्त महानिदेशक संजय ब्रह्मणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कपिल मांगलिक और एफओआई लोकेश रामपाल शामिल हैं। यह पैनल जनशक्ति नियोजन, परिवर्तनशील ज़रू रोस्टरिंग प्रणालियों और पायलटों के लिए नवीनतम ड्यूटी अवधि और विश्राम मानदंडों को लागू करने के लिए एयरलाइन की तत्परता की बारीकी से जाँच करेगा।डीजीसीए प्रमुख फैज़ अहमद किदवई द्वारा 5 दिसंबर को घोषित, यह पैनल इंडिगो द्वारा संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा प्रावधानों के अनुपालन की भी समीक्षा करेगा। इसमें एयरलाइन द्वारा स्वीकार की गई कमियों का आकलन और व्यापक व्यवधानों के परिणामस्वरूप योजनागत विफलताओं के लिए जवाबदेही तय करना शामिल है।

विविध समाचार

बंगाल में बाबरी के शिलान्यास के जवाब में गूँजा गीता पाठ, साधु-संतों ने गीता पाठ के जरिये दिया तुष्टिकरण की राजनीति को जवाब

कोलकाता ०८/१२ (संवाददाता): कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार को लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक माहौल रचा, जब 'पंच लाखो कोंठे गीता पाठ' (पांच लाख स्वरों द्वारा गीता पाठ) कार्यक्रम में साधु संतों, महात्माओं और भक्तों ने एक स्वर में भगवद्गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। हम आपको बता दें कि 'सनातन संस्कृति संसद' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य और देशभर के अनेक मठों के संत सज़्मिलित हुए। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, विधायक और अन्य राजनीतिक हस्तियाँ भी शामिल हुई, यद्यपि मंच पर इसके आध्यात्मिक स्वरूप पर ही बल दिया गया। यह आयोजन ऐसे समय हुआ जब एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में

'बाबरी मस्जिद' की तर्ज़ पर एक मस्जिद की नींव रखी थी। यह एक ऐसा कदम था जिसे व्यापक रूप से राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित, साज़्प्रदायिक तनाव भड़काने वाला और धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक दोहन माना गया। इसी पृष्ठभूमि में कोलकाता के मैदान में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ और संतोंङ्कमठों की एकजुट उपस्थिति ने एक वैकल्पिक संदेश दिया कि धर्म को राजनीति की सेवा में नहीं, बल्कि समाज की शांति, सामंजस्य और सांस्कृतिक गौरव के उत्थान के लिए खड़ा होना चाहिए।

कार्यक्रम में गीता के प्रथम, नवम और अठारहवें अध्याय का सामूहिक पाठ हुआ। भगवा वस्त्रों में साधु-संतों का उमड़ा समुद्र, लहराते तिरंगे और 'हरे कृष्ण' भजन की गूँज, इन सबने यह स्पष्ट संकेत दिया कि बंगाल की सांस्कृतिक चेतना राजनीति की सीमाओं से कहीं व्यापक है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि बंगाल धार्मिक अहंकार को समाप्त करने और बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए धर्म की पुनर्स्थापना के महत्व पर बल दिया। वहीं, भाजपा नेताओं ने आयोजन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में चित्रित करते हुए तृणमूल सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर तृणमूल नेता कुनाल घोष ने इसे गीता का 'राजनीतिक दुरुपयोग' बताया। देखा जाये तो हुमायूं कबीर द्वारा 'बाबरी शैली' की मस्जिद का शिलान्यास स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक दांव था यानि धार्मिक भावनाओं को उकसाकर लाभ लेने की कोशिश। ऐसे कदम न केवल समाज में विभाजन की रेखाएँ गहरी करते हैं, बल्कि धर्म को चुनावों और नीतिगत संघर्षों का हथियार बना देते हैं। लेकिन ठीक इसी नकारात्मक राजनीति के तुरंत बाद, बिना किसी प्रतिशोधी भाषा, नारों या भीड़-उन्माद के संतों, महात्माओं और लाखों श्रद्धालुओं ने गीता पाठ के माध्यम से जो उज़र दिया वह कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण था। यह प्रतिक्रिया टकराव की नहीं, सनातन की शक्ति और भारतीय संस्कृति की स्वाभाविक समावेशिता की थी।

देखा जाये तो जहाँ हुमांयू कबीर का कदम धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक प्रोपगेंडा बनाने का प्रयास था, वहीं गीता पाठ का विराट आयोजन इस बात की घोषणा थी कि धर्म राजनीति का उपकरण नहीं, बल्कि समाज का नैतिक आधार है। जब लाखों कंठों ने एक साथ गीता के श्लोक पढ़े, तो वह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। वह बंगाल के आध्यात्मिक चरित्र की पुनर्स्मृति थी, एक संदेश कि राजनीतिक उकसावों से परे भी समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान में एकजुट खड़ा हो सकता है। संतोंङ्कमहात्माओं का यह शांत लेकिन प्रभावी उज़र यह भी दर्शाता है कि सनातन परंपरा की शक्ति किसी विरोध या हिंसा में नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा और सांस्कृतिक निरंतरता में निहित है। वह राजनीतिक बयानबाज़ी का जवाब राजनीतिक भाषा में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों की स्वाभाविक उजास से देते हैं। यही भारतीय संस्कृति की परिभाषित करने वाली शक्ति है जहाँ उज़र तलवार से नहीं, बल्कि श्लोक से दिया जाता है; जहाँ विभाजन का जवाब एकता से दिया जाता है।

गोवा में नाइट ज़्लब में आग लगने से लोगों की मौत अत्यंत दुखद : शाह

नयी दिल्ली ०८/१२ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गोवा के एक नाइट ज़्लब में आग लगने की घटना में लोगों की मौत 'बेहद दुखद' है। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन बचाव एवं राहत अभियान संचालित कर रहा है और प्रभावितों को आवश्यक देखभाल प्रदान कर रहा है। शाह ने 'एज़्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना में लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है। स्थानीय प्रशासन बचाव एवं राहत अभियान संचालित कर रहा है और प्रभावितों को आवश्यक देखभाल प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, ''मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति हैं, जिनके प्रियजनों ने इस हादसे में जान गंवाई है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'' रोमियो लेन स्थित एक नाइट ज़्लब 'बिर्च' में मध्यरात्रि के बाद लगी आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर उज़री गोवा के अरपोरा गांव में स्थित यह पार्टी स्थल पिछले साल ही खुला था। घटनास्थल पर पहुंचे मुज़्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मृतकों में ज़्यादातर लोग ज़्लब की रसोई में काम करने वाले कर्मचारी थे, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मरने वालों में तीन से चार पर्यटक भी शामिल हैं।

नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने किया सस्पेंड, लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप

०८/१२ (संवाददाता): नवजोत कौर सिद्धू को उनके विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह सिद्धू के उस विवादित बयान के कुछ ही घंटों बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह पंजाब का मुज़्यमंत्री बन जाता है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कौर ने शनिवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं...लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं जो हम मुज़्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें।सिद्धू पर बात करते हुए नवजोत कौर ने दावा किया कि सिद्धू का कांग्रेस के प्रति लगाव तो बहुत है लेकिन

उन्हें कभी मुज़्यमंत्री पद नहीं मिलेगा। मीडिया ने सवाल किया ज़्यों नहीं मिलेगा? जवाब में नवजोत बोली मुज़्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ लगते हैं और हमारे पास देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। इसी के साथ सिद्धू के वापस बीजेपी जाने के सवाल पर नवजोत ने कहा कि मैं खुल के बोलती हूं वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड है। बहुत ज़्यादा उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है। पर मुझे इतनी इनफैज़्टिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणी से पता चलता है कि कांग्रेस में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति मुज़्यमंत्री बनने के बारे में तभी सोच सकता है जब उसके सूटकेस में 500 करोड़ रुपये हों। कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट आचरण में डूबी हुई है। पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके दावे को कांग्रेस के लेन-देन की राजनीति के इतिहास से जोड़ा।

1 लाख लोग करेंगे कुरान का पाठ, टीएमसी के निलंबित विधायक ने दिया बड़ा बयान

कोलकाता ०८/१२ (संवाददाता): नई बाबरी पर हुमायूं कबीर का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है 1 लाख लोग कुरान का पाठ करेंगे। ये बड़ी खबर है। चावल और मांस का भोज होगा। हुमायूं कबीर ने कहा। हुमायूं कबीर ने आगे यह भी कहा है कि उन्होंने गीता पाठ किया। अब हम कुरान का पाठ करेंगे। दरअसल हमने कल देखा था कि कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ किया गया था। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि उन्होंने गीता पाठ किया था। तब इसके बदले में हम यहां पर कुरान का

पाठ करेंगे और जो भोज होगा उसमें बांस और चावल होगा। सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। कबीर ने कहा कि फरवरी में कुरान पाठ के बाद बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू होगा।

कबीर ने इससे पहले 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ के दिन मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी थी।

टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी विरोधी गतिविधियों और सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस बीच, विभिन्न मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों के साधु और आध्यात्मिक नेताओं के समूह सनातन संस्कृति संसद ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में %पंच लाखो कंठे गीता पाठ% (पांच लाख आवाजों द्वारा गीता पाठ) का आयोजन किया गया। कोलकाता में आयोजित सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार %कट्टरपंथी शक्तियों% को बढ़ावा दे रही है और हिंदू समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता शामिल हुए। आयोजकों ने इसे आध्यात्मिक आयोजन बताया, हालांकि इसके राजनीतिक मायने भी चर्चा में है।

आमिर खान और जावेद अख्तर ज़्या मराठी बोलते हैं-नितेश राणे

मुंबई ०८/१२ (संवाददाता): महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) से कथित रूप से जुड़े लोगों के एक समूह द्वारा मीरा रोड में एक दुकानदार पर मराठी न बोलने के कारण हमला करने के कुछ दिनों बाद, राज्य के मंत्री नितेश राणे ने उन्हें चुनौती दी कि वे साहस दिखाएं और नल बाज़ार और मोहज़्मद अली रोड जैसे इलाकों में जाएं और वहां लोगों से मराठी बोलने के लिए कहें।

घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राणे ने सवाल किया कि मराठी न बोलने वाली मशहूर हस्तियों को कभी निशाना ज़्यों नहीं बनाया जाता।नितेश राणे ने कहा कि एक हिंदू को मराठी न बोलने पर पीटा गया। अगर उनमें हिज़्मत है, तो नल बाज़ार, मोहज़्मद अली रोड पर जाएं और वहां लोगों से मराठी बोलने को कहें। उनमें इतनी हिज़्मत नहीं है कि वे वहां जाकर टोपी पहनने वालों को पीटें। ज़्या जावेद अज़्तर और आमिर खान मराठी बोलते हैं? एक गरीब हिंदू को ज़्यों पीटा जा रहा है? आक्रामक लहजे में राणे ने आलोचकों को सरकार के धैर्य की परीक्षा न लेने की चेतावनी दी और कहा कि इससे उन्हें अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।काशीमीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, कथित तौर पर एमएनएस बैज पहने सात अज्ञात लोग सुबह करीब 10.30 बजे दुकान में पानी मांगने घुसे। कथित तौर पर दूसरे राज्य से आए एक कर्मचारी ने हिंदी में जवाब दिया, जिससे दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

विजयन ने कांग्रेस नेता वेणुगोपाल की सार्वजनिक बहस की चुनौती स्वीकार की

तिरुवनंतपुरम ०८/१२ (संवाददाता): केरल के मुज़्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को कहा कि वह संसद में राज्य के विपक्षी कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ)के सांसदों के प्रदर्शन पर सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसी के साथ विपक्षी मोर्चे से इसके लिए तारीख और समय तय करने का आग्रह किया। मुज़्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव के सी वेणुगोपाल के बयान के संबंध में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़्या विजयन इस मामले पर खुली बहस के लिए तैयार हैं।

वेणुगोपाल का बयान वरिष्ठ वाम नेता द्वारा की गई हालिया आलोचना के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूडीएफ सांसद संसद में केरल के विकास के मुद्दों को उठाने में विफल रहे हैं और कई अवसरों पर राज्य के हितों के खिलाफ रुख अपनाया है।

विजयन ने कहा, ''निश्चित रूप से मैं (खुली बहस के लिए) तैयार हूं। उन्हें

समय और स्थान तय करने दीजिए।'' उन्होंने सवाल किया कि ज़्या वेणुगोपाल को राज्य के यूडीएफ सांसदों के प्रदर्शन की जानकारी नहीं है।मुज़्यमंत्री ने यूडीएफ सांसदों पर केरल को बर्बाद करने की केंद्र सरकार की कोशिशों में साथ देने का आरोप लगाया। विजयन ने दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने केंद्र को राज्य के खिलाफ रुख अपनाने की सलाह भी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में केरल को अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किए जाने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद में कुछ प्रश्न उठाकर राज्य में सभी एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) राशन कार्डों को समाप्त करने का प्रयास किया।

सीजेआई ने हरियाणा की जेलों में कौशल विकास और पॉलिटेज़्निक पाठ्यक्रमों का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली ०८/१२ (संवाददाता): हरियाणा की विभिन्न जेलों में कैदियों के लिए को कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेज़्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम और आईटीआई स्तर के व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए गए।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुग्राम के जिला कारागार भोंडसी से 'सलाखों के पीछे जीवन को सशक्त बनाना, वास्तविक परिवर्तन- सुधारात्मक न्याय का नया प्रतिमान' परियोजना के तहत इन पहलों का उद्घाटन किया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस सुधारात्मक प्रयास के तहत हरियाणा की

जेलों में कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेज़्निक डिप्लोमा कार्यक्रम और आईटीआई स्तर के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किए गए।

इन पहलों का उद्देश्य व्यवस्थित ढांचागत शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से सुधारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार देना था। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक महीने तक चलने वाले राज्यव्यापी नशा विरोधी जागरूकता अभियान का भी आरंभ किया, जिसे राज्य में मादक द्रव्यों के सेवन की बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया था।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

खिल उठेगा गेंदा

थावडरी मिलड्यू- इस बीमारी के कारण पत्तियों, शाखाओं एवं पुष्प कलियों पर सफेद फफूंदी का जमाव होता है। जो बाद में भूरे रंग का हो जाता है। जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। और अन्ततः पौधा सूख जाता है। इस बीमारी का प्रकोप फरवरी माह से प्रारंभ होता है।

उपचार- रोग की रोकथाम हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

विषाणु रोग (वायरस)- इस बीमारी के प्रकोप से पत्तियों पर हरे रंग का चितकबरा पड़ जाता है। जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा पुष्प बहुत कम या छोटे आकार के लगते हैं। आमतौर पर इसका प्रसारण संपर्क, हाथों, फसल के अवशेषों , कृषि के यंत्रों तथा कीट द्वारा होता है।

उपचार-रोगोर 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। 800 से 1000 लीटर पानी का घोल बनाकर प्रति हेक्टर खड़ी फसल में छिड़काव करें।

गेंदा फसल में निम्नलिखित प्रमुख कीट लगने की संभावना होती है-

माइट (मकड़ी)- गेंदा फसल पर पत्तियों की निचली सतह पर लाल रंग की मकड़ी जाल बनाकर रहते हैं। जो पत्तियों तथा पुष्प कलिकाओं/फूलों से रस चूसते रहते हैं। जिससे पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है। तथा पुष्प कलिका खिल नहीं पाती पत्तियों पर बना हुआ जाला पौधे की बढ़वार में बाधक होता है।

उपचार- इसकी रोकथाम हेतु रोगोर 0.3 प्रतिशत या मेलाथियान 0.2 प्रतिशत के घोल का छिड़काव पत्तियों के दोनों तरफ करें।

बडवोर्म (कलिका वेधक)- इस कीट की इल्लियां पुष्प कलिकाओं में छिद्र करके घुस जाती है व अन्दर ही अंदर पुष्प की पंखुड़ियों को खा जाती है। जिससे पुष्प खिल नहीं पाते है। एवं पुष्पों का बाजार भाव कम हो जाता है।

उपचार- इसित कलिकाओं / पुष्पों को एकत्र करके नष्ट कर दें। इल्लियों को हाथ से पकड़कर नष्ट किया जा सकता है। फसल समाप्त होने पर खेत की गहरी जुताई करके प्यूपा को नष्ट कर दें। फसल पर प्रकोप दिखाई देते ही क्विनालफास 0.7 प्रतिशत का छिड़काव आवश्यकतानुसार करें।

हापर (फुदका)- इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों की मुलायम का रस चूसते हैं। फलस्वरुप पत्तियां सिकुड़ जाती है। जो बाद में पीली पड़कर गिर जाती हैं।

उपचार- कीट के नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच खेतों में लगायें चाहिए। फसल में कीट का प्रकोप दिखाई देने पर रोगोर/ डेमोक्रान 0.5 प्रतिशत का घोल का छिड़काव 10-15 दिन के अंतर में 2-3 बार करें।

खेतिहर बैलों की देखभाल

सबेरे से शाम तक कृषि कार्य में इस्तेमाल किए गये औजार जू कंधों पर ढ़ोने से उसके कंधों में भी दर्द उत्पन्न होता हैं। अगर हम बैल की ओर यह सब सोचकर नये दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह महसूस होगा। अत: उसकी उचित देखभाल तथा प्रबंधन करने से बैलों की थकान मिटाई जा सकती हैं तथा समुचित पोषण प्रबंधन द्वारा उसकी जो ऊर्जा खर्च होती हैं उसकी भरपाई की जा सकती है। ऐसा न करने पर कुपोषण, गलन प्रबंधन अधूरी देखभाल से बैलों की कार्यक्षमता कार्य उत्पादन स्वास्थ्य पर विपत्ति असर पड़ता हैं। अत: यह सब टालने हेतु उनका निम्नलिखित अनुसार प्रबंधन करें-

आवास प्रबंधन- बैलों को अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है और इससे वे थककर चूर हो जाते हैं। अतः शाम को घर लौटने के बाद उन्हें आराम प्रदान करने हेतु आरामदायक आवास निहायत जरुरी हैं। आवास ऊंचाई पर, साफ-सुथरी जगह, सुखे स्थान पर, प्रकाशमान हवादार होना चाहिए। आवास में बैल सबसे ज्यादा समय जमीन के संपर्क में रहते हैं अतः जमीन कठोर उबड़-खाबड़ पत्थर कंकड़ों से भरी कीचड़ भरी नहीं होनी चाहिए। फर्श नर्म मुलायम सूखा, साफ समतल आरामदेह होना चाहिए। फर्श पर पत्थर या पत्थर की गोटियां जो बहुत गर्म होती है या सर्दियों में बर्फ के समान ठंडी होती हैं बैलों के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होती। उन पर लगातार बैठने से उनके बदन में जाती पैदा होती है। यहां तक की लगातार कई दिनों तक ठंडे फर्श पर बैठने से उन्हें लकवे की शिकायत भी हो सकती है। ऐसा होने पर कीमती बैल बेकाम हो जाते हैं। अतः जमीन घुम्मस कर समतल बना लें। वह न तो कठोर होना चाहिए और न ही कीचड़ भरी हो। बाड़े की दीवार बाड़े के मध्य में 15 फीट ऊंची तथा बगलों में 10 फीट ऊंची होनी चाहिए। बाड़े के इर्द-गिर्द छायादार वृक्ष लगायें ताकि बैल उनकी ठंडी छाया में बैठकर विश्राम कर सकें बाड़े में पीने के लिए साफ, ठंडा ताजा जल उपलब्ध करवायें।

पोषण प्रबंधन-बैल मेहनती कार्य करते हैं अतः उनकी ऊर्जा, प्रोटीन तथा खनिज लवणों की आवश्यकताएं पूर्ण होना जरुरी हैं। इसके लिए उन्हें पौष्टिक तथा आहार उनके कार्य अनुसार खिलाना चाहिए। अगर बैल साधारण कम मेहनती कार्य कर रहा है तो उसे 5 किलोग्राम चारे की कुट्टी, 20 किलो हरा चारा तथा 2 से 3 किलोग्राम खुराक प्रतिदिन खिलायें। अगर वह ज्यादा कठोर परिश्रम कर रहा है तो उसे 10 किलो चारे की कुट्टी, 25 किलो हरा चारा जिसमें बरसीम या ल्यूसर्न या अन्य कोई पत्तीदार वनस्पति का चारा जो प्रोटीनयुक्त, पौष्टिक होता हैं खिलाना चाहिए। इसके अलावा उनके आहार में प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खाद्य नमक तथा 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण होना चाहिए। उन्हें भरपेट यांछित मात्रा में पानी पिलायें। गर्मियों में पानी पिलाने से पहले थोड़ा गुड़ खिलायें।

प्रबंधन- बैलों के प्रबंधन में कई बातें होती हैं। उन्हें तेज धूप होने पर खेत में कार्य हेतु न भेजें। सबेरे पांच बजे से सबेरे नौ या कम धूप होने पर 10 बजे तक तथा शाम को सूरज की रोशनी कम होने पर 2 से 3 घंटे कृषि कार्य हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें थकान कम होगी, कम कष्ट होगा तथा कार्य उत्पादन ज्यादा होगा।

बैल जब काम करने के बाद थक जाते हैं तब वे हांफने लगते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगता हैं। उनके कार्य की गति कम हो जाती हैं यह सब अनुभव से जाना जा सकता हैं। ऐसी स्थिति आने पर उन पर रहम करें और थोड़ी देर के लिए काम रोक दें। उनकी गर्दन से जू हटाकर उन्हें किसी छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने दें। थोड़ी देर बाद पानी पिलायें। कुछ हरा चारा तथा कुछ सूखा चारा खिलायें। अगर उन्हें मुट्ठीभर नमक तथा कुछ गुड़ खिलाकर पानी पिलायें तो बहुत बेहतर होगा और ऊर्जा प्राप्त होगी। इससे वे तरोताजा हो जायेंगे और विश्राम के बाद नये उत्साह तथा उमंग से फिर कार्य कर पायेंगे। इससे उनसे थोड़ा ज्यादा कार्य करवा सकेंगे।

शाम को घर लौटने के बाद उनकी पीठ तथा विशेषकर कूबड़ को गर्म पानी से धीरे-धीरे मलकर धोयें। इसके अलावा पीठ तथा कुण्ड को गुनगुने तेल में कपूर मिलाकर उससे धीरे-धीरे रगड़कर मालिश करें। इससे बैलों को काफी आराम महसूस होगा तथा उनकी थकान दूर हो जायेगी। वे तरोताजा होकर नये उत्साह तथा उमंग से कार्य करेंगे। गर्मियों में कृषि कार्य से निवृत होने के बाद बाड़े में लौटने के कुछ देर बाद उन्हें ठंडे पानी से नहलाएं तथा उनका बदन पीठ तथा कूबड़ धीरे-धीरे रगड़कर मालिश करें।

बैलों के शरीर पर हर हफ्ते खरहरा करें। इससे उनके शरीर की मालिश हो जायेगी जिससे उनके शरीर में खून का संचार अच्छी तरह होगा। खरहरा करने से उनकी त्वचा में लसिका ग्रंथियों का स्त्रवण भी सुचारु रुप से होगा जिससे उनकी त्वचा चमकदार और मुलायम तथा निरोगी रहेगी। खरहरा करने से उनके बदन पर अगर जूं, किलनी, लीचड़, पिस्सू आदि बाह्य परजीवी मौजूद हो तो वह भरी निकल जायेंगे। खरहरा करने के कई लाभ हैं और खर्च कुछ भी नहीं। अतः इस बिना खर्च की तकनीक का अवश्य इस्तेमाल करें।

कभी-कभी कोई किसान किसी कारणवश खरहरा नहीं कर पाते या पशुओं के झुंड बड़े होने से बाह्य परजीवियों का प्रकोप हो गया तो डेल्टामेथ्रीन युक्त खास पशुओं के लिए बनी अलग दवा होती हैं फसलों के ऊपर छिड़काव करने वाली ज्यादा स्त्रान्द दवा तथा पंप इस कार्य हेतु इस्तेमाल न करें। 2 मिलीलीटर दवा एक लीटर पानी में घोलकर उसका बैलों के शरीर पर अच्छी तरह छिड़काव करें। विशेषकर जाघों में, सींगों के नीचे, कानों के नीचे दुम के नीचे अच्छी तरह छिड़काव करें क्योंकि इन स्थानों पर बाह्य परजीवी विशेष रुप से बहुतायत में रहते हैं।

बैलों को पेट के कृमियों को मारने वाली दवा जैसे अल्बेंडाझाल या थाईबेंडाझाल 3 महीने में एक बार पिलावें। इससे पेट के कृमियों का नाश होगा। इसके अलावा बैलों को बरसात शुरू होने से पहले हर वर्ष खुरपका-मुंहपका रोग, गलाघोंटू रोग, जहरी बुखार तथा लंगडा रोड इन रोगविरोधी टीके अनुभवी पशुचिकित्सक द्वारा लगवायें।

उनके खुरों की रोजाना जांच करें। अगर उनमें कांटे लगे है तो चिमटे से निकालकर वहां जंतुनाशक मरहम लगायें। अगर बैल सुस्त दिखाई दें तो अनुभवी पशुचिकित्सक द्वारा जांच करवाकर दवा का बंदोबस्त करें। उनके बाड़े में कीचड़ कतई न होने दे अन्यथा वे ठीक से आराम नहीं कर पायेंगे और आराम ना होने पर तरोताजा नहीं हो पायेंगे और दूसरे दिन सुस्त महसूस करेंगे तथा खेत में ठीक से कार्य नहीं कर पायेंगे। कीचड़ में कई तरह के कीड़े भी पैदा होते है तो बैलों को परेशान करते हैं काटते हैं जिससे उनमें थाइलेरियासिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अतः जब बैल खेत में निकल जाते हैं तब सूखा मुरम डालकर कीचड़ पर परत लगवायें। बाड़े से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। बाड़ें से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। बाड़े में कड़वे नीम, तुलसी की पत्तियां निलगिरी की पत्तियां जलाकर धुआ करें जिससे कीड़ों का प्रकोप कम होगा। बाड़े में कीटनाशी दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं।

बैलों को मारपीट न करें। कुछ किसान एक लकड़ी में कील लगाकर उससे उन्हें चुभाते हैं जिससे उनके पार्श्व भाग पर जख्म होते हैं। वहां कीड़े भी लग सकते हैं। अतः वहां जंतुनाशक घोल से जख्म साफ कर मरहम लगवायें। कुछ परेशानी होने पर, अत्यधिक थकान के कारण बैल कार्य करते वक्त रुक सकता हैं। अतः उक्त कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करें।

बैल किसान का मित्र हैं अतः उसकी उपरोक्त लिखित अनुसार देखभाल एवं प्रबंधन करें तो वह स्वस्थ एवं निरोग रहेगा। उसकी कार्यक्षमता बरकरार रहेगी और वह अच्छी तरह कार्य का निष्पादन अच्छी तरह कर पायेगा।

कलिंग समाचार

संपादकीय

मंगलवार 09 दिसंबर 2025

देश सेवा-नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी

भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व घटना हुई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर 1 घंटे 11 मिनट तक कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 22 पन्नों का प्रजेंटेशन दिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इस सीट पर 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस के शोध में यहां एक लाख के करीब गलत पते और एक ही पते पर थोक मतदाताओं और नकली मतदाताओं का पता चला। जिसका पूरा खुलासा राहुल गांधी ने किया था। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में मतदाता सूची में हेर फेर करके भाजपा ने चुनाव जीता है, यह आरोप तो विपक्ष पहले से लगा रहा था। लेकिन यह पहली बार था जब किसी एक सीट का इस तरह पूरा कच्चा-चिठ्ठा मीडिया के जरिए देश के सामने रखा था। राहुल गांधी के इस खुलासे के फौरन बाद ही चुनाव आयोग ने इस पर फेक और मिसलीडिंग यानी फर्जी और भ्रामक होने का ठप्पा तो लगा दिया, साथ ही एक प्रेस कांफ्रेंस कर मु य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने कहा था। जबकि राहुल गांधी का कहना था कि वे कोई हलफनामा पेश नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी बात सबूतों के साथ रखी है, अब दारोमदार चुनाव आयोग पर है कि वह इसे या तो गलत साबित करे या फिर अपनी गलती माने। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी महीने की 4 तारीख को राहुल गांधी ने दो और प्रेस वार्ताएं की और उन दोनों में फिर से इसी तरह की मतदाता सूची की गड़बड़ी को दिखाया, जिसके बूते भाजपा ने चुनाव जीता। राहुल गांधी केवल मुंहजबानी आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि सबूतों के साथ उसे मीडिया के सामने रख रहे हैं। अपनी तीनों प्रेस वार्ताओं में राहुल मंच पर अकेले ही थे और पत्रकारों को खुला अवसर दिया गया कि वे राहुल गांधी से प्रश्न-प्रतिप्रश्न करें, उन पर तीखे सवाल दागें, उन पर आरोप लगाएं कि कांग्रेस कई राज्यों में हार चुकी है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। यानी पत्रकारों के पास पूरा मौका था कि वे अपने सवालों से राहुल गांधी को ऐसा घेरें कि उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाए। लेकिन ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है जब राहुल गांधी के पास कोई जवाब न हो, या अपने बचाव में सामने रखने के लिए तथ्य न हों। आंकड़ें, तथ्य और सबूत तीनों से लैस होकर ही राहुल गांधी ने पत्रकारों का सामना किया, इसलिए अब तक किसी ने भी उन्हें गलत साबित नहीं किया। जबकि भाजपा ने चुनाव आयोग पर लगते हर आरोप पर आगे बढ़कर सफाई दी और इसमें राहुल गांधी पर निशाना साधा कि वे संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं। अब भाजपा का परोक्ष साथ देते हुए 272 लोगों का एक खुला खत सामने आया है। खुद को नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी का नुमांइदा बताने वाले इस खत के हस्ताक्षरकर्ताओं में सेवानिवृत्त जज, नौकरशाह, सैन्य अधिकारी शामिल हैं। खत में कहा गया कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार-बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। इस खुली चिट्ठी में लिखा है कि पहले सेना, फिर न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए, और अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। यह एक खतरनाक चलन बन गया है, जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, उसे गद्दार तक कहा और अधिकारियों को धमकाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा पेश नहीं किया। यह सिर्फ राजनीतिक नाराजगी है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। जब विपक्षी पार्टियां जीतती हैं, तब चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन हार मिलते ही आयोग को दोषी ठहराना शुरू हो जाता है। यह राजनीतिक अवसरवाद है। चिट्ठी में लिखा है कि टीएन शेषन और एन गोपालस्वामी जैसे पूर्व मु य चुनाव आयुक्तों ने आयोग को बेहद मजबूत और निष्पक्ष संस्था बनाया है, इसलिए आज उस पर बेबुनियाद हमले लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हैं।

ईमानदारी और निर्भयता से जीना क्या इतना कष्टप्रद हो रहा?

डॉ. प्रितम भि. गेडाम

जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तब वह केवल अपना स्वार्थ साबित नहीं करता, बल्कि वह किसी अन्य का हक अनुचित तरीके से छिनता है, देश के विकास और सुव्यवस्था में अड़चने पैदा करता है, समाज में अपराध के बीज बोता है, साथ ही अन्याय करके पीड़ितों के सपनों को कुचलता है, जिसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, भ्रष्टाचार के कारण कई बार पूरे समाज को दशकों तक दुःख-दर्द झेलना पड़ता हैं।

भ्रष्टाचार के कारण असंख्य मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, संघर्षमय जीवन का चक्र अतितीव्र होते जाता हैं। सभी नागरिकों को विकसित होने का मौका मिलता है, समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहती हैं।

कानून और सरकारी यंत्रणा इसके मजबूत स्तंभ है, जो हर पायदान पर नागरिकों के अधिकारों, सरकारी कार्यों एवं उपक्रमों का योग्य क्रियान्वयन कर विकास की नित नई कहानी लिखते हैं। अगर इस सुशासन में एक भी कड़ी अपनी जि मेदारी से पल्ला झाड़ कर खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करने लगे तो, संबंधित अनेक विभागों के लिए वह नासूर का काम करता है और धीरे-धीरे पूरे विभाग को खोखला कर देता हैं। ऐसा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी समाज, सरकार, देश और समस्त मानवजाती का दुश्मन होता हैं। बहुत बार खबरों में देश के कई मामूली सरकारी कर्मचारी, नेता धनकुबेर जैसे अरबों का धन छुपाये बैठे है, ऐसा पता चलता हैं।

हमारा समाज और हम आधुनिकता का दम भरने वाले निकृष्ट सोच वाली विचारधारा के लोग किस विश्वसनीयता के स्तर पर आ गए है? मौलिकता, नैतिकता, सहजता, जागरूकता, नीतिमत्ता, निस्वार्थता, परोपकारिता, संस्कारशीलता, ईमानदारी को छोड़कर बुराई, कपट और स्वार्थ प्रवृत्ति को तेजी से अपना रहे हैं। लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि, अनुचित कार्य या अपराध होने पर भी लोग अपराधी का पक्ष लेने के लिए उतारू हो जाते हैं।

कुछ दिन पूर्व मैं एक श स से मिला, उस श स ने पैसे को लेकर अपने विचार मुझसे साझा किये, उन्होंने कहा कि, पैसा ही भगवान है, पैसा ही सब कुछ है, चाहे वह किसी भी मार्ग से आये, पैसे से इज्जत, शोहरत, नाम होता है, हर चीज खरीद सकते है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, तो हम क्यों ईमानदारी दिखाए? कोई नहीं पूछता कि पैसा किस मार्ग से कमाया, पैसे के लिए अपराध करों, जेल जाओ, सजा भुगतो, लेकिन पैसा आने के बाद लोग आपके अपराध भी भूल जाते है, उन्हें सिर्फ पैसा

दिखाई देता हैं। लोगों की इतनी खराब सोच तो सीधे-सीधे देश में कानून व्यवस्था को झुठलाकर अपराधीकरण को बढ़ावा देनेवाली है, ऐसे में तो हर ओर जंगलराज स्थापित होगा। आज देश में इस प्रकार के विचारधारा के लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही हैं। देश में हम कई बार देखते है कि चुनाव में संगीन गुनाहों के अपराधी उ मीदवार को भी जनता चुनकर लाती है और दूसरी ओर उच्च शिक्षित निरपराध ईमानदार समाजसेवी उ मीदवार की जमानत भी जप्त हो जाती हैं।

हमारे आसपास समस्याओं का अंबार लगा है, अक्सर भ्रष्टाचार और अनियमितता का बोलबाला हर ओर हम देखते है, अधिकतर लोग बुराई के खिलाफ आवाज उठाना पसंद नहीं करते। सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की गैर जिमेदाराना हरकतों के कारण बहुत बार हादसे भी होते है, जिसमे जान-माल का भारी नुकसान होता हैं। हर साल देखते है कि, पहली बरसात में ही सड़कें सरकारी दावों की पोल खोल देती हैं। अरबों रुपये खर्च करके चलने वाली योजनाएं कुछ समय में ही दम तोड़ देती है, तय समयावधि में काम पुरे नहीं होते और उस कार्य का बजट बढ़ते जाता हैं। देश में आर्थिक विषमता की दूरी लगातार बढ़ ही रही हैं। अपने फायदे के लिए पार्टियां बदलने वाले राजनीतिक नेता दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। सरकार के एक भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी अनेक बार मासूमो की जान ले सकती है, भले ही मरने के बाद मृतक के परिवार को थोडासी आर्थिक सहायता दी जाती हो, परंतु मृतक की जान तो लौटकर नहीं आती हैं।

हमारे देश में जितने गरीब किसान आत्महत्या करते है उतने किसी भी दूसरे देश में आत्महत्या नहीं करते, इसके मुकाबले कोई भी अन्य पेशेवर व्यवसायी भी इतनी बड़ी सं या में आत्महत्याएं नहीं करते। चाहे कितने ही घोटाले या आपराधिक गतिविधियों में नाम आ जाए फिर भी देश को चलाने वाले नेता लोग इतना तनाव भी नहीं लेते कि आत्महत्या करनी पड़े।

ईमानदार व्यक्ति के हाथों अनजाने में छोटी सी भूल भी हो जाये तो बहुत पछतावा महसूस करते है, परंतु अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करने वाले भ्रष्ट लोग सुकून से जी कैसे लेते है? लोगों से नजरे मिलाकर स्वाभिमान से बात कैसे कर लेते है? परिवार, रिश्ते, अपनों के सामने आदर्श कैसे स्थापित करते है? क्या लोगों का जमीर मर चुका है? वस्तुएं, सेवाएं, रिश्ते-नाते में भी अब मिलावट नजर आता है, कब कौन धोखा दे जाये, कह नहीं सकते।

आत्मसन्मान, इंसानियत, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, सामाजिक जि मेदारी, नैतिकता का कोई मोल नहीं बचा? लोगों को दुख देकर बदले में हम अपना सुख खरीद नहीं सकते। सुकून भरी नींद, स्वाभाविक खुशी, निस्वार्थ प्रेम, मानसिक शांति और समाधानी मन से बढ़कर जीवन में कुछ अन्य की जरुरत नही है, यही असली आनंद है, जो हमें अपने आचरण द्वारा प्राप्त होता हैं। रोजाना अखबार और समाचार चैनलों पर बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की खबरे रहती हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी भ्रष्टाचार का दंश झेलते हुए आगे बढे है, भ्रष्टता स पूर्ण व्यवस्था को खत्म करने की ताकत रखती है, अगर इसे सत्ता की ताकत मिल जायें तो उस देश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता।

लोग जागरूक बनें, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझें। इंसान के रूप में जन्म लिया है तो इंसानियत का फर्ज निभाएं। दूसरे का हक छीन कर नहीं बल्कि ईमानदार और परोपकारी की भूमिका निभानी चाहिए। जो व्यक्ति जितने ऊंचे जि मेदार पद पर कार्यरत होता है, वह जनता के लिए उतना ही ज्यादा जवाबदेही होता है, जनता उससे नहीं बल्कि उसने जनता से डरना चाहिए, अगर अनुचित कार्य करें तो। जनता अपने कर द्वारा सरकार को आर्थिक ताकत प्रदान करती है, जनता को अधिकार है कि वह जि मेदार अधिकारी या नेताओ को उत्तर मांगे।

अपराधी और अनुचित कार्य करने वाले लोग डरकर रहना चाहिए ना कि स य और ईमानदार लोग डर-डर कर जियें। भ्रष्टाचार करनेवाला व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के लिए लाभ मांगता है लेकिन लाभ देने वाला व्यक्ति भी अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हैं। अगर लाभ देना ही बंद कर दे तो लाभ मांगेगा किससे भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने की जि मेदारी हर नागरिक ने खुद से ही करनी होगी।

अपने देश के लिए भले ही थोड़ी तकलीफ सहनी पड़े, लेकिन देश का आनेवाला भविष्य बेहतर होगा, भावी पीढ़ी को उनका हक मिलेगा। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी शाखाएं जनता के मदद के लिए तत्पर है, उनकी मदद लें। हम उनसे ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। रिश्वत न दें, न लेने दें, सतर्क रहें। राष्ट्रहित में सहयोग करें।

बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए बनाया गया दवा बाजार

आर. सूर्यमूर्ति

हर देश आखिरकार यह तय करता है कि हेल्थकेयर एक अधिकार है या कमाई का ज़रिया। भारत ने बहुत लंबे समय तक यह दिखाने की कोशिश की है कि वह दोनों हो सकता है। कमेटी ने आखिरकार इस धोखे का पर्दाफाश कर दिया है। अब यह सरकार पर है कि वह टूटी हुई मूल्य निर्धारण व्यवस्था में सुधार करेगी- या उस इंडस्ट्री को बचाती रहेगी जिसने नियामक कमज़ोरी को आर्थिक हक समझ लिया है। किसी भी मायने में, भारत बीमार लोगों के लिए दुनिया की सबसे सस्ती जगह होनी चाहिए। यह जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। फिर भी आम भारतीयों के लिए, असल अनुभव इसके उलट है- एक हेल्थकेयर सिस्टम जहां एक साधारण बुखार की दवा की कीमत उसकी आपूर्ति की कीमत से छह गुना, गैस्ट्रिक की गोली की कीमत दस गुना, और एक जान बचाने वाली कैंसर की दवा की कीमत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसकी छपी हुई अधिकतम खुदरा कीमत से लगभग 80 प्रतिशत कम हो सकती है। यह साफ है कि इस बाजार को इलाज तक जनता की पहुंच और उनकी खर्च वहन करने की क्षमता के अनुरूप नहीं, बल्कि उनका दोहन कर भारी लाभ अर्जित करने के अनुरूप बनाया गया है।

केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पर स्टैंडिंग कमिटी की ताजा रिपोर्ट अपने डायग्नोसिस में बहुत स त है, परन्तु अभी भी उसमें पर्याप्त कठोरता नहीं है। कमिटी ने उस बात को बहुत ध्यान से दस्तावेज के रूप में रिकार्ड किया है जो मरीज़ दशकों से जानते हैं- कि भारत की दवाओं की मूल्य निर्धारण प्रणाली दवा निर्माता कंपनियों के लिए एक खुला मैदान है, खासकर उन बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए जिनके ब्रांडेड जेनेरिक उस श्रेणी की दवाओं पर हावी हैं जिन पर लोग हर दिन भरोसा करते हैं। कमिटी लिखी गयी कीमतों को अतार्किक, बहुत ज़्यादा, और जनहित के खिलाफ कहती है। यह तो ठीक है। असलियत इससे भी बुरी है- पूरी प्रणाली निर्धारित मूल्य मुद्रास्फीति, नियामक की अनुपस्थिति, और एक राजनीतिक प्रतिष्ठान पर बना है जो एक ऐसे उद्योग का सामना करने को तैयार नहीं है जो बिना किसी सज़ा के बहुत ज़्यादा सहजता से काम कर रही है।

रिपोर्ट में दिए गए नंबर चौंकाने वाले हैं। 21 रुपये की एमआरपी वाली एक आम एंटीहिस्टामाइन टैबलेट एक स्टॉकिस्ट को मात्र 1 रुपये 85 पैसे में दी जाती है— जो 1,038 प्रतिशत है। एक स्टैंडर्ड एसिड-रि लक्स दवा जिसकी कीमत 170 रुपये है, डिस्ट्रीब्यूटर को मात्र 13.95 रुपये की पड़ती है, जो 1,119 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। एक आम तौर पर लिखी जाने वाली कैल्शियम सप्लीमेंट की कीमत में तो हद हो गयी है- 16.95 रुपये की आपूर्ति कीमत के मुकाबले एमआरपी 327 रुपये है, यानी 1,831 प्रतिशत का मार्जिन। ये कभी-कभार होने वाली गड़बड़ियां नहीं हैं; ये बिजनेस मॉडल है। कमेटी ने एलर्जी, गैस्ट्रो, विटामिन, कार्डियोवैस्कुलर और बच्चों की दवाओं में भी ऐसी ही गड़बड़ियां पाईं- दूसरे शब्दों में, ये भारत की दवाइयों की टोकरी का दिल हैं।

सबसे ज़्यादा ज्यादतियां ऑन्कोलॉजी में दिखती हैं- जहां दांव सचमुच ज़िंदगी और मौत का होता है। कैंसर की एक दवा, जिसका एमआरपी 38,215 रुपये है, ऑनलाइन 9,200 रुपये में बिकती है। दूसरी, जिसकी आनलाइन उपलब्ध लिस्ट पर मूल्य 45,000 रुपये है, रिटेल में 8,800 रुपये में मिलती है। दुनिया का कोई भी भरोसेमंद मूल्य निर्धारण इकोसिस्टम इतना ज़्यादा अंतर नहीं दिखाता, जब तक कि मूल कीमत को बनावटी तौर पर न बढ़ाया जाए। कमेटी, जो आमतौर पर अपनी भाषा को लेकर सावधान रहती है, यहां ईमानदारी से कहती है- %ये एमआरपी ज़्यादा ट्रेड मार्जिन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।% जब कोई मरीज़ परेशान होता है, जब परिवार किसी को ज़िंदा रखने के लिए अपनी संपत्ति बेच रहे होते हैं या अपनी बचत खर्च कर रहे होते हैं, तो कंपनियों को पता होता है कि वे बिना किसी नतीजे के कीमतें बढ़ा सकती हैं। फिर सरकार, जो इस पैटर्न को पूरी तरह जानती है, नज़रअंदाज़ कर देती है।

ऐसा नहीं है कि भारत में दखल देने के लिए कानूनी ढांचा नहीं है। उसके पास एनपीपीए है, जो एक मूल्य नियंत्रक है; ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर है, जो एक कानूनी ढांचा है; और सस्ती दवाओं के लिए एक घोषित राष्ट्रीय वायदा है। लेकिन उसके पास हि मत नहीं है। एनपीपीए एक बिना दांत वाला वॉचडॉग है। यह दवा उत्पादन लागत का ऑडिट नहीं कर सकता।

यह कॉस्ट शीट की मांग नहीं कर सकता। यह ट्रेड मार्जिन के खुलासे को ज़रूरी नहीं कर सकता। यह किसी भी नॉन-शेड्यूल्ड दवा की लॉन्च प्राइस को नियंत्रित नहीं कर सकता— जो एक ऐसी श्रेणी है जो आसानी से भारत के दवा बाजार के 85 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से में छाया रहता है। ज़्यादा जानें क्षेत्रीय समाचार कवरेज अंतरराष्ट्रीय समाचार समाचार पत्र कविता संग्रह पुस्तकें बॉलीवुड समाचार संग्रह क्षेत्रीय समाचार पत्र पेपर ई-पेपर एक्सेस कविता संग्रह खेल समाचार अपडेट इस बीच, सरकार जन औषधि को जनता की क्रय शक्ति की पहुंच में रखने की अपनी प्रतिबद्धता के सुबूत के तौर पर पेश करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जन औषधि नीति की जीत नहीं बल्कि उसका दोष है। जब वही मॉलिक्यूल सरकारी दुकान पर 12 रुपये में बिकता है जिसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी 170 रुपये में बेचती है, या जब कोई सप्लीमेंट जो सरकारी फार्मेसी में 40 रुपये में बिकता है, उसकी कीमत ब्रांडेड लेबल के तहत 327 रुपये हो, तो नतीजा साफ़ है- बहुत ज़्यादा एमआरपीन तो स्वाभाविक हैं और न ही ज़रूरी। लेकिन उनकी इजाज़त है। अस्पताल इन नियंत्रित कीमतों के ऊपर जीएसटी, प्रोसिजरल फीस और पैकेज चार्ज लगा रहे हैं, और चुपचाप उसी बोझ को फिर से बढ़ा रहे हैं जिसे खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। जब दखल प्रतीकात्मक हो जाता है, तो मुनाफाखोरी ढांचागत हो जाती है। असली दुखद बात यह है कि सरकार ट्रेड मार्जिन रैशनलाइज़ेशन पर पूरी तरह से फेल है। जब टीएमआर को कुछ समय के लिए 42 कैंसर दवाओं पर लागू किया गया, तो एमआरपी50 प्रतिशत तक गिर गए। मरीजों ने एक साल में लगभग 984 करोड़ रुपये बचाए। जब महामारी के दौरान कुछ मेडिकल डिवाइस पर टीएमआर लागू किया गया, तो इससे और 1,000 करोड़ रुपये की बचत हुई। फिर भी टीएमआर पांच साल से रुका हुआ है, मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स और उनके घरेलू सहयोगियों के भारी असर वाले कंसल्टेशन में फंसा हुआ है। कमेटी इस सच्चाई का सीधे तौर पर नाम नहीं लेती है, लेकिन इंसेंटिव्स को समझने के लिए किसी फोरेंसिक ऑडिटर की ज़रूरत नहीं है। भारत एक ग्लोबल फार्मा पावरहाउस बनने के लिए पागल है, लेकिन अगर वह अपने देश में प्राइसिंग पावर के गलत इस्तेमाल का सामना करने से इनकार करता है, तो वह एक ही समय में दुनिया का आपूर्तिकर्ता और अपनी आबादी का रक्षक नहीं हो सकता।

यह उलटापन बहुत अजीब है- भारत 200 से ज़्यादा देशों को कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है, लेकिन उसके अपने नागरिक अक्सर उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए कहीं ज़्यादा पैसे देते हैं। देश अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ-ईस्ट एशिया में सस्ती दवाइयां निर्यात एक्सपोर्ट करता है, जबकि घरेलू डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को ऐसे मार्जिन कमाने की इजाज़त देता है जिन्हें उन्हीं देशों में अनैतिक माना जाएगा - अगर गैर-कानूनी नहीं तो। भारत के पास दवा की कीमतों पर डेटा की कमी नहीं है- उसके पास फैसले लेने की कमी है। यह शर्म की बात है कि कैंसर की दवाओं की कीमतें लग्ज़री चीज़ों की तरह हैं। यह भी शर्म की बात है कि बहुत ज़्यादा एमआरपीइसलिए बनी हुई हैं क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले मरीज का पक्ष लेने से इनकार करते हैं। हर देश आखिरकार यह तय करता है कि हेल्थकेयर एक अधिकार है या कमाई का ज़रिया। भारत ने बहुत लंबे समय तक यह दिखाने की कोशिश की है कि वह दोनों हो सकता है। कमेटी ने आखिरकार इस धोखे का पर्दाफाश कर दिया है। अब यह सरकार पर है कि वह टूटी हुई मूल्य निर्धारण व्यवस्था में सुधार करेगी- या उस इंडस्ट्री को बचाती रहेगी जिसने नियामक कमज़ोरी को आर्थिक हक समझ लिया है। अगर भारत सच में दुनिया की फार्मेसी बनना चाहता है, तो उसे पहले अपने ही लोगों को दिवालिया बनाना बंद करना होगा।

विविध समाचार

चंडीगढ़ का सीरियल किलर दोषी करार, एमबीए छात्रा सहित 3 महिलाओं का किया मर्डर, 12 साल बचता रहा

चंडीगढ ०८/१२ (संवाददाता): चंडीगढ़ में 15 साल पहले एमबीए छात्रा की रेप के बाद हुए मर्डर केस में कोर्ट ने सीरियल किलर मोनू को दोषी करार दे दिया है। अब उसे कल सजा सुनाई जाएगी। जिस वक्त उसे दोषी करार दिया गया, कोर्ट में छात्रा के माता–पिता भी मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई लेकिन सजा का इंतजार करने की बात कही है। यह मामला 2010 का है।

जब छात्रा के कत्ल के 12 साल तक आरोपी का पता ही नहीं चल सका था। पुलिस ने भी अनट्रेस केस की रिपोर्ट दाखिल कर दी थी और परिवार ने भी न्याय की आस छोड़ दी थी। मगर, साल 2022 में चंडीगढ़ में ही हुई एक महिला की हत्या की जांच में पुलिस के हाथ छात्रा के मामले का पहला सुराग लगा।

पुलिस की ओर से कराए गए 100 से ज्यादा डीएनए टेस्ट और 800 लोगों से हुई पूछताछ में आरोपी मोनू कुमार निवासी डड्डूमाजरा शाहपुर कॉलोनी, चंडीगढ़ का नाम सामने आया। मगर, दिक्कत ये थी कि वह चंडीगढ़ छोड़कर बिहार जा चुका है और ना तो वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, ना उसके पास आधार कार्ड था और ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट। ऐसे में पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। मगर, साल 2024 में वह चंडीगढ़ लौटा तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने दोनों महिलाओं की हत्या की बात कबूली। यह भी बताया कि 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।

एनएचपीसी ने मनाया संविधान दिवस : नए लेबर कोड्स पर जागरूकता सत्र आयोजित, अधिकारियों को पढ़ाए गए नियम

चंडीगढ़ ०८/१२ (संवाददाता): एनएचपीसी क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के कार्मिकों ने कार्यपालक निदेशक श्री आदित्य गौतम के अगुवाई में संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावना पाठन किया। इस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 को लागू की गई श्रम संहिताएं लागू करते हुए कार्य बल के लिए श्रम संहिताएं जागरूकता सत्र का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत श्री एम एम खान, समूह वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा चारों श्रम संहिताओ यथा मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंधा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 के विषय पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। कार्यपालक निदेशक महोदय ने इस जागरूकता सत्र को सबके लिए लाभकारी तथा ज्ञानवर्धक बताया, उन्होंने प्रतिभागियों को इसके शत प्रतिशत अनुपालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए । इस सत्र में समूह महाप्रबंधक (विधि) श्रीमती रूबी रैना, उप महाप्रबंधक (वित्त) श्री राजेंद्र सिंह रावत एवं उप महाप्रबंधक (सिविल) श्री वीरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियो तथा कर्मचारियों ने भी सहभागिता की। सभी उपस्थित कार्मिकों ने इस जागरूकता सत्र को बहुत सराहा तथा इसे सबके लिए लाभप्रद बताया।

पंजाब का मूर्तिकार बना रहा धर्मेंद्र का स्टैच्यू, जानें कितना आएगा खर्च, कितनी होगा लंबाई और चौड़ाई ?

मोगा ०८/१२ (संवाददाता): बॉलीवुड के 'ही–मैन' और पंजाब के पुत्र धर्मेंद्र के निधन से जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक शोक में डूबे हैं, वहीं उनके गृह राज्य पंजाब में उन्हें एक अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि देने की तैयारी चल रही है। मोगा जिले के गांव मानुके के रहने वाले मशहूर मूर्तिकार इकबाल सिंह गिल ने अपने चहेते सितारे की यादों को हमेशा के लिए सहेजने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने धर्मेंद्र की एक भव्य प्रतिमा तैयार करने का काम शुरू कर दिया है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। इकबाल सिंह गिल इस कार्य को अभिनेता के प्रति अपने सम्मान के रूप में देख रहे हैं। मूर्तिकार इकबाल सिंह गिल ने बताया कि वे अपनी कला के जरिये इस दिग्गज अभिनेता को नमन कर रहे हैं और धर्मेंद्र का यह स्टैच्यू लगभग एक सप्ताह के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रतिमा को बनाने में आने वाला करीब एक लाख रुपये का पूरा खर्च इकबाल सिंह खुद वहन करेंगे। स्टैच्यू की लंबाई और चौड़ाई पूरी तरह से धर्मेंद्र की कद–काठी के हिसाब से ही रखी जा रही है ताकि दर्शकों को अभिनेता की जीवंत छवि का अहसास हो सके। तैयार होने के बाद इस स्टैच्यू को इकबाल अपनी आर्ट गैलरी में स्थापित करेंगे, जो कला प्रेमियों और धर्मेंद्र के फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इकबाल सिंह का कहना है कि धर्मेंद्र पंजाब की मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे और भले ही आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हर पंजाबी के दिल में हमेशा रहेंगे। इकबाल को बचपन से ही मूर्तियां बनाने का शौक था और महज 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की बनाई थी। खेती–बाड़ी के साथ–साथ उन्होंने मूर्तिकला को अपना जुनून और पेशा दोनों बनाया है। उनका मानना है कि जो लोग देश का मान बढ़ाते हैं, उन्हें अपनी कला के माध्यम से श्रद्धांजलि देना उनका कर्तव्य है। बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र का यह स्टैच्यू उनकी कला को एक नई पहचान देगा। इकबाल सिंह गिल के हुनर की चर्चा दूर–दूर तक है और उनके हाथों से बनीं सैकड़ों मूर्तियां आज देश–विदेश की कई संस्थाओं और स्थानों पर स्थापित हैं। धर्मेंद्र से पहले वे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, महान एथलीट मिल्खा सिंह, दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला, कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबियां, बाबा लाडी शाह और कई शहीद फौजियों की प्रतिमाएं बना चुके हैं। गौरतलब है कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हो गया था।

जालंधर वेस्ट में 13 वर्षीय बच्ची के परिवार से मिले नितिन कोहली, तेज न्याय और फास्ट–ट्रैक कोर्ट में कार्यवाही का भरोसा

जालंधर ०८/१२ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल हल्का प्रभारी नितिन कोहली बुधवार को जालंधर वेस्ट में 13 वर्षीय पीड़ित बच्ची के परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मीडिया से बातचीत में कोहली ने कहा कि परिवार जिस असहनीय दर्द से गुजर रहा है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मामला फास्ट–ट्रैक कोर्ट में सुना जाए, ताकि न्याय में देरी न हो। कोहली ने कहा, "हम परिवार के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। आरोपी किसी भी स्थिति में नहीं बचेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि यह मामला फास्ट–ट्रैक कोर्ट में चले, ताकि दोषी को बिना देरी सबसे कठोर दंड मिल सके।" उन्होंने यह भी कहा कि जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आएगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। " माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस भी पुलिस कर्मी की लापरवाही इस घटना में उजागर होगी, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी," कोहली ने कहा। जालंधर मेयर वनीत धीर भी इस दौरे में शामिल रहे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि नगर निगम प्रशासनिक स्तर पर हर सुविधा और सहायता तत्काल उपलब्ध कराएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पंजाब सरकार के कला और पर्यटन सलाहकार दीपक बाली ने भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, "सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी। हम जनता के साथ खड़े हैं। यह किसी दल या सरकार का मुद्दा नहीं, बल्कि जनता का मुद्दा है।" पंजाब के मंत्री और जालंधर वेस्ट के विधायक मोहिंदर भगत ने घटना की तीखी निंदा की। भगत ने कहा, "बच्ची केवल 13 वर्ष की थी। वह अपनी सहेली से मिलने गई थी और उसकी इतनी अमानवीय हत्या कर दी गई। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? हम परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि दोषियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा।" भगत ने कहा कि परिवार ने पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं कृ "परिवार का कहना है कि पुलिस कर्मी लगभग आधे घंटे तक आरोपी के घर के भीतर रहे, लेकिन बच्ची को ढूंढ नहीं पाए और परिवार को अंदर जाने से रोका। यह स्पष्ट लापरवाही है। ऐसी लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होना तय है। हम इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे।" उन्होंने परिवार को पूर्ण कानूनी और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। "हम परिवार के लिए श्रेष्ठ वकील की व्यवस्था करेंगे। यदि आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, तो वह भी उपलब्ध कराई जाएगी।

पराली जलाने की आग में झुलसता उत्तर भारत : समाधान किसानों और पर्यावरण दोनों के हित में

चंडीगढ। हर वर्ष जब धान की कटाई का मौसम आता है, तब पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठने वाला धुआँ आसमान को धुंध से भर देता है। यह केवल खेतों की आग नहीं होती, बल्कि भारत की कृषि नीति, आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय असंतुलन की जलती हुई तस्वीर होती है। दिल्ली तथा उसके आस–पास के क्षेत्र इस धुएँ से ढक जाते हैं और वायु गुणवत्ता अत्यंत गंभीर स्तर तक पहुँच जाती है। कानूनी रूप से पराली जलाना प्रतिबंधित है, फिर भी किसान इसे हर साल दोहराते हैं क्योंकि इसके पीछे अनेक सामाजिक और आर्थिक कारण जुड़े हैं। पराली जलाने का मूल कारण खेतों में बचा हुआ धान का ठूँठ होता है। जब धान की फसल कट जाती है, तब खेत में रह गए अवशेष को हटाने के लिए किसानों के पास न समय होता है न साधन। पंजाब और हरियाणा की कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से धान और गेहूँ पर आधारित है। सन् 1960 के दशक की हरित क्रांति ने इन राज्यों को देश का अन्न भंडार तो बना दिया, परंतु कृषि को एकरूपी और जलदृप्रधान भी बना दिया। भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सन् 2009 में पंजाब में "उपदृजल संरक्षण अधिनियम" लागू किया गया, जिसके अंतर्गत धान की रोपाई जून के अंत तक करने का निर्देश दिया गया ताकि मानसूनी वर्षा का लाभ लिया जा सके। परिणामस्वरूप धान कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच केवल दस से बीस दिन का अंतर रह गया। इतने कम समय में किसान पराली को एकत्रित या सड़ाकर खेत तैयार नहीं कर सकते, इसलिए वे सबसे तेज और सस्ता उपायकृजलानाकृचुन लेते हैं। दूसरा बड़ा कारण आर्थिक है। पराली हटाने या निपटाने के लिए जो मशीनें चाहिएकृजैसे सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली, हैप्पी सीडर, बेलर या रोटावेटरकृवे अत्यंत महँगी हैं। छोटे और सीमांत किसान जिनकी जोत तीन हेक्टेयर से भी कम है, वे इन मशीनों को खरीदने या किराए पर लेने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, हैप्पी सीडर का किराया लगभग दो से तीन हजार रुपये प्रति एकड़ पड़ता है, जबकि पराली जलाने में केवल माचिस और थोड़े डीजल का खर्च आता है। यही व्यावहारिकता इस समस्या को गहराई तक जकड़े हुए है। तीसरा कारण पराली का कम उपयोग मूल्य है। पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली अधिकतर धान की किस्में साधारण होती हैं, जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ऐसी पराली पशु चारे के रूप में प्रयोग योग्य नहीं होती और न ही इससे जैव ईंधन या खाद आसानी से बनाई जा सकती है।

पूर्वी भारत के राज्यों में धान की पराली पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में आती है, परंतु पंजाबदृहरियाणा में यह उपयोग सीमित है। इसीलिए यहाँ पराली किसानों के लिए किसी आर्थिक लाभ का साधन नहीं बन पाती। चौथा कारण है श्रम की कमी और जोत का विखंडन। प्रवासी मजदूरों की संख्या घट रही है, और छोटे खेतों में मशीनरी लगाने की क्षमता नहीं है। समय की कमी और श्रमिकों के अभाव में किसान अगली फसल बोने की जल्दी में पराली को जला देते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी पराली जलाना वर्षों से एक स्वीकृत प्रक्रिया बन चुकी है। किसानों को यह लगता है कि खेत की सफाई का यही सबसे आसान और पारंपरिक तरीका है। कानूनों और जुर्मानों के बावजूद यह प्रथा इसलिए जारी है क्योंकि प्रवर्तन ढीला है और राजनीतिक दबावों के कारण प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं कर पाता। वर्ष 2023 में पंजाब में लगभग साठ हजार पराली जलाने की घटनाएँ दर्ज की गईं, जबकि जुर्माना और निगरानी दोनों व्यवस्था में थे। स्पष्ट है कि केवल प्रतिबंध या दंड इस समस्या को समाप्त नहीं कर सकते। आवश्यक है कि ऐसी रणनीति अपनाई जाए जो किसान की आजीविका और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चले। पहला समाधान है फसल विविधीकरण। पंजाब और हरियाणा की भूमि लगातार धानदृगेहूँ चक्र से थक चुकी है। जल स्तर भी नीचे जा रहा है। अतः मक्का, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन फसलों के लिए यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीमा सुरक्षा और निश्चित खरीद सुनिश्चित करे तो किसान धीरे–धीरे धान पर निर्भरता कम कर सकते हैं। हरियाणा की "भावांतर भरपाई योजना" इस दिशा में एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें किसानों को मूल्य अंतर की भरपाई दी जाती है। दूसरा समाधान है यंत्रीकरण और साझा संसाधन। किसानों को मशीनें साझा उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएँ। पंचायत या सहकारी समितियों के स्तर पर "कस्टम हायरिंग केंद्र" स्थापित हों, जहाँ से किसान कम किराए पर हैप्पी सीडर या सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली जैसी मशीनें ले सकें। केंद्र सरकार की "फसल अवशेष प्रबंधन योजना" के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा में एक लाख से अधिक मशीनें बाँटी गई हैं, पर इनकी पहुँच सभी किसानों तक नहीं हो पाई है। यदि हर गाँव में सामुदायिक यांत्रिक केंद्र बने, तो किसान पराली जलाने से बचेंगे। तीसरा उपाय है पराली का औद्योगिक उपयोग। पराली को कचरा न मानकर एक संसाधन के रूप में देखा जाए। इससे जैव ऊर्जा, एथेनॉल, कागज, पैकेजिंग और निर्माण सामग्री तैयार की जा सकती है। उदाहरण के लिए, भारतीय तेल निगम की पानीपत जैव रिफाइनरी प्रतिवर्ष लगभग दो लाख टन पराली से एथेनॉल बनाती है। यदि इस प्रकार की परियोजनाएँ हर जिले में स्थापित हों तो पराली किसानों के लिए आय का स्रोत बनेगी और जलाने की आवश्यकता कम होगी। सरकार को परिवहन सहायता, खरीद अनुबंध और स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की नीति बनानी चाहिए। चौथा कदम होना चाहिए कृषिदृपर्यावरणीय समय निर्धारण। धान की छोटी अवधि वाली किस्में जैसे पी.आर.126 या डी.आर.आर. धानदृ44 अपनाने से किसानों को फसल कटाई और बुवाई के बीच कुछ अतिरिक्त दिन मिल सकते हैं।

इस समय का उपयोग पराली प्रबंधन में किया जा सकता है। इसके साथदृसाथ परिशुद्ध कृषि यानी सटीक तकनीकी साधनों का प्रयोग, जलदृसिंचाई प्रणाली में सुधार और जैविक खाद उपयोग से भी पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। पाँचवाँ, सामुदायिक प्रोत्साहन और जनजागरूकता। पराली न जलाने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए, गाँव स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित हो और "शून्य दहन ग्राम" घोषित किए जाएँ। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में "पुसा डीकंपोजर" नामक जैविक घोल के प्रयोग से पराली को खेत में ही खाद में बदला जा रहा है। यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो पराली जलाने की आवश्यकता नहीं बचेगी। छठा, प्रशासनिक तालमेल और नीतिदृसमन्वय। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य होना चाहिए ताकि कृषि, पर्यावरण और ऊर्जा विभाग एक साझा योजना के अंतर्गत काम करें। पराली प्रबंधन को ग्रामीण रोजगार योजना, जैव ऊर्जा मिशन और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मनरेगा के अंतर्गत पराली एकत्रीकरण या जैव खाद इकाइयों में कार्य को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। सातवाँ, शहरीदृग्रामीण सहभागिता भी इस दिशा में उपयोगी होगी। दिल्ली जैसे महानगर जहाँ प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव होता है, उन्हें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से पंजाबदृहरियाणा के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, मंगलवार 09 दिसंबर 2025 | पृष्ठ-6

समलेई प्रोजेज़्ट के दूसरे चरण को पूरा करने का लक्ष्य अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया

संबलपुर ०८/१२ (संवाददाता): मां समलेश्वरी मंदिर के आसपास समलेई प्रोजेज़्ट के दूसरे चरण को पूरा करने का लक्ष्य अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है, ज़्योंकि ज़मीन से जुड़े मुद्दों के कारण मार्च 2026 की पिछली डेडलाइन के मुकाबले काम में देरी हुई है। मंदिर के रीडेवलपमेंट प्लान का दूसरा चरण, जो 83 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, अभी 16वीं सदी के मंदिर के पास चल रहा है। इसमें भक्तों और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई टूरिज्म और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बनाई जा रही हैं। काम करने वाली एजेंसी ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रज़्शन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने पुष्टि की कि प्रस्तावित ओपन-एयर थिएटर सहित कुछ हिस्सों के लिए साइट अलॉटमेंट में चुनौतियों के कारण डेडलाइन को बदला गया है। पिछले हज़्ते, संबलपुर के कलेज़्टर सिद्धेश्वर बलिराम बोंदर ने प्रोजेज़्ट साइट का दौरा करके स्थिति की समीक्षा की और चल रहे कामों की स्थिति का जायजा लिया। समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष संजय बाबू ने कहा, ज़मीन के एडजस्टमेंट सहित सभी पिछली बाधाएं दूर हो गई हैं और काम में तेज़ी आई है। पिछली योजना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि भक्तों की बढ़ती संज़्या को देखते हुए यात्री निवास को दो मंजिला सुविधा में बदलना। हमें उज़्मीद है कि हम संशोधित समय सीमा के भीतर प्रोजेज़्ट पूरा कर लेंगे, उन्होंने आगे कहा।दूसरे चरण के हिस्से के रूप में, चेरुआपाड़ा के पास नौ एकड़ के तालाब पर एक बोटिंग ज़ोन विकसित किया जा रहा है ताकि मंदिर परिसर के पास आने वाले लोगों को मनोरंजक वॉटर राइड का अनुभव मिल सके। दूसरी तरफ, शाम के मुज़्य आकर्षण के रूप में एक ज़्यूजिकल फाउंटेन बनाया जा रहा है। मंदिर के चारों ओर आराम करने की जगह और एक खास शाम का माहौल बनाने के लिए एक इंटरनल प्लाज़ा, रास्ते, फूड कोर्ट और बच्चों के पार्क पर भी काम चल रहा है।ओपन-एयर थिएटर (एज़्फीथिएटर) के लिए ज़मीन पहले ही पहचान ली गई है, जहाँ मंदिर के त्योहारों से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन होंगे। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ाव लगभग पूरा हो चुका 200 बिस्तरों वाला यात्री निवास है, जिससे दूर-दराज के भक्तों और पर्यटकों के लिए रहने की सुविधा में काफी सुधार होने की उज़्मीद है। प्रोजेज़्ट का पहला चरण, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में हुआ था, ने मंदिर के चारों ओर एक व्यापक बदलाव किया, जिसमें एक नया बैरिकेड, पोडियम, ज़्लोकरूम, वेंडर ज़ोन, सूचना केंद्र, तीर्थ यात्रा सुविधा केंद्र, मंदिर तालाब, भोग मंडप, हेरिटेज कॉरिडोर, खोंडालाइट पत्थर के रास्ते, मंडप, डेक स्पेस और बड़ा पार्किंग क्षेत्र शामिल हैं। लगभग 40 एकड़ में फैला, डेवलपमेंट प्रोजेज़्ट पहले फेज में 250 करोड़ रुपये और चल रहे दूसरे फेज में 83 करोड़ रुपये के बजट के साथ पूरा किया जा रहा है।

आरएसपी के जन स्वस्थ विभाग द्वारा डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए व्यापक थर्मल फॉगिंग अभियान शुरू

राउरकेला ०८/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर अभियांत्रिकी विभाग के जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा 21 नवंबर को वर्षा ऋतु के बाद शहर में डेंगू और अन्य मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के उद्देश्य से व्यापक थर्मल फॉगिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। सेज़्टर-5 स्थित जन स्वास्थ्य विभाग परिसर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महाप्रबंधक (नगर अभियांत्रिकी), श्री हर प्रसाद पटनायक ने की और फॉगिंग वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुज़्य चिकित्सा अधिकारी (नगर इंजीनियरिंग- जन स्वास्थ्य), डॉ. दीपा लवंगारे सहित जन स्वस्थ विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

चारों वाहन प्रतिदिन निर्धारित समय-सारणी के अनुसार इस्पात शहर के विभिन्न सेज़्टरों में जाकर अलग-अलग ज़्लॉकों को कवर करेंगे। इन वाहनों में से एक वाहन संबंधित क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में फॉगिंग कार्य करेगा।

उल्लेखनीय है कि, जन स्वस्थ इकाई हर वर्ष इस्पात नगरी में बड़े मच्छरों की संज़्या को नियंत्रित करने के लिए फॉगिंग अभियान चलाती है। यह एहतियाती कदम डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दीपा लवंगारे द्वारा किया गया।

शिक्षकों की कमी से सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमरायी

राउरकेला ०८/१२ (संवाददाता): राउरकेला नगर निगम एवं बिसरा ज़्लाक क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संज़्या लगातार बढ़ रही है। परए शिक्षकों की संज़्या में लगातार कमी आने के कारण शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। तीन साल के अंदर ज़्लाक के 80 से अधिक शिक्षक सेवानिवृज़ हुए हैं। ज़्लाक में छह साल से नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। 2015 में केवल 10 शिक्षक अनुबंध पर नियुक्त हुए हैं। ज़्लाक में प्राथमिक विद्यालयों में 12 हजार 942 विद्यार्थी हैं। वहींए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 9268 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं होने से अभिभावकों में असंतोष देखा जा रहा है। राउरकेला नगर निगम तथा बिसरा ज़्लाक क्षेत्र के स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की काफी कमी है। जितने शिक्षक सेवानिवृज़ हो रहे हैं उतने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। वर्ष 2020 में ज़्लाक क्षेत्र से 44 शिक्षक सेवानिवृज़ हुए हैं। वहींए 2021 में 39 शिक्षक सेवानिवृज़ हुए। 2022 में चार शिक्षक सेवानिवृज़ हुए हैं।

आगामी दिसंबर तक 50 से अधिक शिक्षक सेवानिवृज़ होंगे। तीन साल में सवा सौ से अधिक शिक्षकों के सेवानिवृज़ होने के बाद भी उसकी तुलना में नियुक्ति काफी कम है। 2015 में अनुबंध पर 10 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इसके छह साल बाद एक भी नियुक्ति नहीं हुई। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षकों की संज़्या कम होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इससे अभिभावकों में असंतोष देखा जा रहा है। सरकार की ओर से स्कूलों के रूपांतरण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं पर शिक्षक नियुक्ति की दिशा में कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। कोट रू बिसरा ज़्लाक में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरु की गई है। शीघ्र ही इसके लिए कदम उठाया जाएगा एवं शिक्षकों की कमी दूर होगी।. अमूल्य प्रधानए जिला शिक्षा अधिकारी।

बणई अनुमंडल में पर्यटन स्थलों की उपेक्षा

राउरकेला ०८/१२ (संवाददाता): प्राकृतिक मनोरम स्थलों से परिपूर्ण बणई अनुमंडल में पर्यटन की उपेक्षा की जा रही है। पर्यटन विभाग व वन विभाग की ओर से खंडाधार जलप्रपातए देवधरए तथा कोइड़ा में प्राकृतिक पर्यटन स्थल के विकास के लिए काम हुआ है पर अब भी गुरुंडिया के बादल गिरि जलप्रपातए ब्राहमणी नदी में सिचाई परियोजनाए सरसरा में सिचाई परियोजनाए कोइड़ा में कुराड़ी नाले में सिचाई परियोजना का काम कर आसपास के क्षेत्र में पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं।

गुरुंडियाए लहुणीपाड़ाए कोइड़ व बणई ज़्लाक के जल प्रपात हैं जिनका विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जा सकता है। सुंदरगढ़ जिले में बणई अनुमंडल में ही ओडिशा का सबसे ऊंचा जलप्रपात खंडाधार स्थित है। राज्य सरकार की ओर से यहां पर्यटको को आकृष्ट करने के लिए इको टूरिज्म में शामिल किया गया है तथा इस क्षेत्र में वन विभाग की ओर से विकास का काम किया जा रहा है।

टेनसा में पहाड़ी की ऊंचाई पर गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं एक महीने के अंदर आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जायेगा। इसके अलावा बणईए गुरुंडियाए लहुणीपाड़ा व कोइड़ा ज़्लॉक क्षत्र में घागए मिरिग लेउटुणीए बादलगिरिए घोराघरए खंभेश्वरीए सूखानालाए मानसमुंडी आदि जल प्रपात लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं। जहां पर्यटन विकास का काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह बणई में तीर्थ घाटए प्राचीन बाबा बणेश्वर मंदिरए राजप्रसादए मा कुमारी मंदिरए जगन्नाथ मंदिरए बीजू पार्कए सानजोलो कलईपोष दर्शनीय स्थल पर्यटकों को आकृष्क नहीं कर पा रहे हैं।

जंगली सूअर किसानों के लिए बन गए हैं बुरा सपना

केंद्रपाड़ा ०८/१२ (संवाददाता): ज़िले के राजनगर और महाकालपाड़ा इलाकों में जंगली सूअरों के उनकी खड़ी धान की फ़सलों को नुकसान पहुँचाने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कई लोगों के लिए, जंगली सूअरों का होना किसी मुसीबत से कम नहीं है, जिससे उन्हें अपने खेतों की रखवाली के लिए रात भर जागना पड़ रहा है। राजनगर ज़्लॉक के राजेंद्रनारायणपुर, गोबिंदपुर, परमानंदपुर, नलितापटिया और दूसरे गाँवों में फ़सलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की खबर है। किसानों का कहना है कि जंगली सूअर अज़्सर अंधेरा होने के बाद खेतों में घुस आते हैं, और कटाई के करीब धान के खेतों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान परेशान हो जाते हैं।एक किसान ने कहा, जंगली सूअर हमारी फ़सलों को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हमें रात में जागकर पहरा देना पड़ रहा है। कोई भी जानवर आ जाए, हमारे पास रात भर अपने खेतों की रखवाली करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आरोप है कि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बार-बार शिकायत करने के बावजूद, प्रभावित किसानों का कहना है कि अब तक कोई सही कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि अधिकारी सुरक्षा के उपाय या मुआवज़ा देने में नाकाम रहे हैं, जिससे नुकसान बढ़ने से उनकी निराशा और बढ़ रही है। जंगली सूअरों का खतरा बना हुआ है, इसलिए किसानों को इस मौसम में पैसे की भारी तंगी का डर है। वे अपनी फसलों को बचाने और यह पक्का करने के लिए कि उनकी रोजी-रोटी और खतरे में न पड़े, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तुरंत दखल देने की मांग कर रहे हैं। बढ़ता तनाव इस बात को दिखाता है कि इस इलाके में इंसान-जानवरों के बीच टकराव को कम करने के लिए मिलकर काम करने की तुरंत ज़रूरत है।

ओडिशा पुलिस के हत्थे चढ़ी नज़सली महिला, 12 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद से थी फ़रार

संबलपुर ०८/१२ (संवाददाता): बीते 12 अप्रैल के दिनए छज़ीसगढ़ के कांकेर में घटित नज़सली और पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद फ़रार महिला नज़सली मांगो नुरेती उर्फ सिंधु को 20 अप्रैल की रातए दक्षिण ओडिशा के नवरंगपुर पुलिस की टीम ने गिरज़्तार कर छज़ीसगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। गौरतलब है कि इस मुठभेड़ में 29 नज़सलियों की मौत हुई थी और इसमें से कुछ दुर्दांत नज़सली नेता भी शामिल थेए इन पर लाखों रुपए का इनाम रखा गया था।इस बारे में जानकारी देते हुए नवरंगपुर जिला पुलिस अधीक्षक रोहित वर्मा ने बताया है कि छज़ीसगढ़ में घटित मुठभेड़ के बाद नज़सलियों के ओडिशा सीमा में घुस आने की आशंका को देखते हुए शनिवार 20 अप्रैल की सुबहए नवरंगपुर जिला पुलिस की ओर से नज़सल विरोधी अभियान शुरु किया गया। इस अभियान में डीवीएफ की दोए एसओजी की एक और सीआरपीएफ 12 वीं बटालियन की टीम शामिल रहीं। इस अभियान के दौरान शाम के समय छज़ीसगढ़ सीमांत पर स्थित नवरंगपुर जिला के कुंदेई थाना इलाके के एक घर से घायल महिला नज़सली मांगो नुरेती उर्फ सिंधु को गिरज़्तार किया गया।पूछताछ के दौरान नवरंगपुर पुलिस को पता चला कि 12 अप्रैल को हुए मुठभेड़ में मांगो उर्फ सिधु भी शामिल थी और घायल होने के बाद फ़रार होकर ओडिशा सीमांत के एक गांव में आकर छिपी थी। इस खुलासे के बाद नवरंगपुर पुलिस ने छज़ीसगढ़ के धमतरी जिला पुलिस से संपर्क कर इस बारे में जानकारी देने समेत उसे आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया।पूछताछ के दौरान नवरंगपुर पुलिस को पता चला कि छज़ीसगढ़ के धमतरी जिला खल्लारी थाना अंतर्गत एकवारी गांव की मांगो नुरेती वर्ष 2021 में सीतानदी एरिया कमेटी में शामिल हुई थी।

सी.पी.पी.-1 में आपातकालीन तैयारी को सुदृढ़ करने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन

राउरकेला ०८/१२ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के पावर एवं ज़्लोइंग स्टेशन (पीबीएस), कैप्टिव पावर प्लांट-1 (सीपीपी -1) के डीएम प्लांट में एसिड रिसाव पर एक मॉक ड्रिल 26 नवंबर, 2025 को की गई, ताकि आपातकालीन तैयारियां को को बढ़ाया जा सके और एसिड रिसाव से होने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयारी पक्की की जा सके। कानूनी ज़रूरत के तहत, यह अज़्यास आरएसपी के ऑनसाइट आपदा प्रबंधन प्रणाली के असर और इसमें शामिल लोगों की तैयारी का अंदाज़ा लगाने के लिए की गई थी। मॉक ड्रिल सुबह 11.10 बजे शुरू हुई, और साइट घटना नियंत्रक, मुज़्य महाप्रबंधक (पावर), और विभागाध्यक्ष सीपीपी -1 श्री दीपक रॉय, ने सुबह 11ः28ः रू बजे स्थिति को नियंत्रण में बताया। पूरे ग्रुप को तीन टीमों में बांटा गया थाः लड़ाकू दल, बचाव दल, और सहायक दल । लड़ाकू दल को सीपीपी -1 के वरिष्ठ प्रबंधक, श्री डी. यादव ने नेतृत्व किया, उनके साथ सीपीपी -1 के जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट, श्री एम. आलम थे, जबकि बचाव दल को सीपीपी -1 के वरिष्ठ प्रबंधक, श्री ए. आनंद ने नेतृत्व किया, उनके साथ सीपीपी -1 के उप प्रबंधक, श्री जे. विष्णुवर्धन थे। सहायक दल को सीपीपी -1 के वरिष्ठ प्रबंधक, श्री सी.के. सिन्हा और सीपीपी -1 के प्रबंधक, श्री ए. जेना ने नेतृत्व किया। सभी टीमों ने अच्छे से काम किया और पूरी अज़्यास 18 मिनट के अंदर सफलतापूर्वक पूरी कर ली। मॉक ड्रिल को महाप्रबंधक (अग्निशमन सेवाएँ), के श्री पी.एस. ठाकरे, उप महाप्रबंधक (अग्निशमन सेवाएँ), श्री एम. सोनकुसरे, और सुरक्षा, अग्निशमन सेवाएँ, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और सीपीपी -1 के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल टीम ने सुरक्षित काम सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके को घेरकर अज़्यास में अहम भूमिका निभाई। अज़्यास के आखिर में, मुज़्य महाप्रबंधक (पावर), और महाप्रबंधक (अग्निशमन सेवाएँ), ने एक समीक्षा किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी अज़्यास की तारीफ़ की और कुछ क्षेत्र में सुधार के सुझाव दिए। इस अज़्यास को महाप्रबंधक (ओ ×एम), सीपीपी -1, श्री एन सी. परिदा, उप महाप्रबंधक (विद्युत) और विभागीय सुरक्षा अधिकारी, सीपीपी -1, श्री आर.के. रंजन, सहायक महाप्रबंधक, सीपीपी -1 श्री डी.के. राउतराय ने मुज़्य महाप्रबंधक (पावर), श्री दीपक रॉय के मार्गदर्शन में समन्वित किया। सी.पी.पी.-1 और सभी संबंधीत विभागों ने सामूहिक भागीदारी द्वारा इस अज़्यास को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।